



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2004/आषाढ़ 28, 1926

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2004/ASADHA 28, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत सम्बन्धी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2004

विषय : चीन जनवादी गणराज्य एवं मलेशिया मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय कम्प्रेसरों के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत

सं. 14/7/2004-डीजीएडी.—मैसर्स बी पी एल इंजीनियरिंग लि., मेडाक, आन्ध्र प्रदेश ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिसूचना, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन रोधी शुल्क कर आकलन और संग्रहण एवं क्षति निर्धारण/नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन और मलेशिया मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय कम्प्रेसरों के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटन रोधी जांच शुरू करने तथा पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद " प्रशीतन करने वाले उपकरण में प्रयुक्त एक किस्म का कम तापमान पर इस्तेमाल होने वाला कम्प्रेसर है (जिसे आगे संबद्ध माल कहा गया है) संबद्ध माल का वर्गीकरण सुमेलीकृत प्रणाली के आधार पर भारतीय व्यापार (वर्गीकरण) में सीमा शुल्क उपशीर्ष 841430 के भीतर किया गया है और 84143000 के भीतर किया गया है। जांच की शुरुआत विचाराधीन उत्पाद के संबंध में की जा रही है, भले ही जिस वर्गीकरण के अंतर्गत उसका आयात किया जा रहा है वह कुछ भी हो। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वह जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इन विशिष्टताओं का निर्धारण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भारतीय मानकों के रूप सुनिर्धारित है और इनकी प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात्

आई एस ओ, डी आई एन, बी एस, ए आर आई, यू एल, ए एस एच आर ए आई और सेकोमैफ से होती है। इसके अतिरिक्त, कम्प्रेसरों का वर्गीकरण अथवा भिन्नता बीटीयू/एचआर के रूप में अलग-अलग ढंग से परिभाषित एवं मुख्यतया मापित प्रशीतन करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। प्रशीतन क्षमता के आधार पर घरेलू अनुप्रयोग वाले कम्प्रेसरों में सामान्य रूप से ऐसे कम्प्रेसर शामिल होंगे जिनकी प्रशीतन क्षमता 200-875 बी टी यू/एच आर है जिनका इस्तेमाल आम तौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है।

2. घरेलू उद्योगों की स्थिति

याचिका मैसर्स बीपीएल इंजीनियरिंग लि., मेडाक, आंध्र प्रदेश द्वारा दायर की गयी है और इसका समर्थन मैसर्स टेकमसेड प्रोडक्ट्स इंडिया लि., बल्लभगढ़, हरियाणा द्वारा किया गया है। आवेदन प्राप्ति के पश्चात् प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध माल के ज्ञात सभी उत्पादकों के बीच मतदान करवाया ताकि नियम 5(3)(क) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य एवं मलेशिया मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के बारे में उनके समर्थन एवं विरोध का पता लगाया जा सके। भारतीय उत्पादन के ब्यौरों और भारत में ज्ञात उत्पादकों से प्राप्त उत्तरों की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है यद्यपि याचिका का समर्थन मैसर्स टेकमसेक प्रोडक्ट्स इंडिया लि., हरियाणा द्वारा किया गया है। उपर्युक्त की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध माल का एक प्रमुख उत्पादक है जिसका भारत में संबद्ध माल के उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और वह उपर्युक्त नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार संबंधी मानदण्ड को पूरा करता है।

3. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया हैं (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है)।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और सम्बद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तुओं के रूप में माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करते हुए मलेशिया में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का दावा किया है और उसने मलेशिया में संबद्ध माल का सामान्य मूल्य

निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों, मजदूरियों, वित्तीय लागतों, विद्युत लागतों, इत्यादि के बारे में समर्थकारी साक्ष्यों के साथ उत्पादन लागत के तत्वों के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है। चीन जनवादी गणराज्य के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना है और सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना है। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि चीन जन.गण. और मलेशिया से संबद्ध माल के लिए किए गए सामान्य मूल्य के दावे के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से संबद्ध माल की निर्यात कीमत का दावा किया है जो आई बी आई एस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना प्रणाली) द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों पर आधारित है। प्राधिकारी द्वारा यह बात नोट की गयी थी कि डी जी सी आई एण्ड एस के आंकड़े उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद में यथाउल्लिखित विभिन्न मॉडलों अथवा विशिष्टताओं के रूप में संबद्ध माल के ब्यौरे प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए निर्यात कीमत किए गए विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक आयातों के अनुसार लिया गया है जिसका चुनाव उपर्युक्त विशिष्टताओं के अनुसार किया गया है। कारखाना द्वार कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और निर्यातक देश में अन्तर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग एवं पत्तन प्रभारों के कारण समायोजन किया गया है।

7. पाटन मार्जिन

इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध माल का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। संबद्ध देशों से आयातों की समग्र मात्रा में वृद्धि, घरेलू बिक्री कीमतों में पर्याप्त गिरावट कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, निवेश में कम आय, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कीमत कम करना जैसे मापदंडों से सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे वास्तविक खतरा बना हुआ है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन रोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 (12 महीने) तक की है।

11. सूचना देना

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, कमरा नं. 243, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएँ।

उपरोक्त नियम को नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिविधिक उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जांच के लिए अनिवार्य सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंचानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2004

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning import of Certain Compressors originating in or exported from China PR and Malaysia.

No. 14/7/2004-DGAD.—M/s. BPL Engineering Ltd., Medak, Andhra Pradesh, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Certain Compressors originating in or exported from China and Malaysia and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present case is "Low temperature application compressors of a kind used in refrigerating equipment" (also referred to as subject goods hereinafter). The subject goods are classified within Customs subheading 841430 and 84143000 in the Indian Trade Classification based on Harmonized system. Investigations are being initiated with respect to product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of these investigations.

The petitioner has claimed that specifications of product under consideration are well laid down as Indian standards by BIS and these are derived from the international standards i.e. ISO, DIN, BS, ARI, UL, ASHRAE and CECOMAF. Further, different compressors are also ranked or differentiated based on their cooling capacity defined variously and principally measured in terms of BTU/hr. Based on the cooling capacity the domestic application compressors would normally include compressors with cooling capacity 200-875 BTU/hr which are commonly used for domestic refrigerators.

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The petition has been filed by M/s BPL Engineering Ltd, Medak, Andhra Pradesh and is supported by M/s Tecumseh products India Limited, Ballabgarh, Haryana. After receipt of the application, the Authority called for opinion of all the known producers of the subject goods in India to determine their support or opposition to the application filed by the petitioner for imposition of Anti dumping duty on

imports originating in or exported from China PR and Malaysia. After examining the details of Indian production and responses from the known producers in India, the Authority notes that the production of the petitioner constitutes a major proportion of the Indian production though the application is also supported by M/s. Tecumseh products India Ltd, Haryana. The Authority after examining the above, determines that the petitioner is a major producer of the subject goods in India accounting for a major proportion of the production of the subject goods in India and therefore the petitioner constitutes a domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and it satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

3. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigation are China PR and Malaysia (hereinafter also referred to as subject countries).

4. LIKE GOODS

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, supra.

5. NORMAL VALUE

The Petitioner has claimed the normal value of the subject goods in Malaysia considering the international price of the raw material and the petitioner has constructed the normal value based on estimates of elements of cost of production along with supporting evidence in respect of raw material prices, wages, financing costs, power costs, etc. to arrive at the normal value of subject goods in Malaysia. In case of China PR, the petitioner has claimed that China PR has to be treated as a non-market economy and normal value has to be determined in accordance with the Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The authority notes that there is sufficient evidence of the Normal value claimed for the subject goods from China PR and Malaysia.

6. EXPORT PRICE

The Petitioner has claimed the export price of the subject goods from the subject countries based on the import data provided by the IBIS (International Business Information System). It was noted by the

Authority that DGCIS data does not give details of the subject goods in terms of different models or specifications as mentioned in the product under consideration above and therefore export price has been taken as per the actual imports made by product under consideration which have been culled out as per the specifications detailed above. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level. There is sufficient evidence of the export price and the adjustments claimed for the subject goods from subject countries.

7. DUMPING MARGIN

There is, prima facie, evidence that the Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

The Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in the absolute volume of imports from the subject countries, increase in the market share of imports from the subject countries in total imports, decline in the import prices from the subject countries, significant decline in the domestic selling price, significant deterioration in profits, cash flow and return on investment, price undercutting, and price depression prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. PERIOD OF INVESTIGATION

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2003 to 31st March 2004 (12 months).

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed

separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Room No. 243, Udyog Bhavan, New Delhi – 1100 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence/application submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority